P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-10* (Part-1) January 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

नांवा तहसील में क्षेत्रीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का शोधपरक अध्ययन

विजय कुमार
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

सारांश

किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास वहाँ के संसाधनों पर तथा उनके जीवन की खुशहाली व सुखी जीवन तथा उस क्षेत्र की अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निर्भर करता है। ये अवसंरचनात्मक सुविधाएं क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की मूलभूत से लेकर आवयक जरूरतों को पूरा करती हैं तथा ये सम्मिलित रूप में सामाजिक सुविधाएं कहलाती हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत न होकर, इनकी प्रकृति सामूहिक सेवा की होती है जो अन्तर सम्बन्धित व अन्तनिर्भर होती हैं। विकसित रूप में ये अवसंरचनात्मक सामाजिक सुविधाएं सेवा केन्द्रों या विकास केन्द्रों के संश्लेषित रूप में क्षेत्र की आवयकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी सेवा व विकास करती है।अध्ययन क्षेत्र में ये अवसंरचनात्मक सुविधाएं विभिन्न कार्यों जैसे शिक्षा व सेवा केन्द्रों, स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, बाजार, विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वच्छता कार्यालय, दुकानों, बैंक पाठषालाऐं आदि के रूप में 193 गांवों मे बिखरी हुई है।

मुख्य शब्द : अवसंरचनात्मक, सुविधाएं, अन्तनिर्भर

प्रस्तावना

किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास वहाँ के संसाधनों पर तथा उनके जीवन की खुशहाली व सुखी जीवन तथा उस क्षेत्र की अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर निर्भर करता है। ये अवसंरचनात्मक सुविधाएं क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की मूलभूत से लेकर आवयक जरूरतों को पूरा करती हैं तथा ये सम्मिलित रूप में सामाजिक सुविधाएं कहलाती हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत न होकर, इनकी प्रकृति सामूहिक सेवा की होती है जो अन्तर सम्बन्धित व अन्तनिर्भर होती हैं। विकसित रूप में ये अवसंरचनात्मक सामाजिक सुविधाएं सेवा केन्द्रों या विकास केन्द्रों के संश्लेषित रूप में क्षेत्र की आवयकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी सेवा व विकास करती है। अध्ययन क्षेत्र में ये अवसंरचनात्मक सुविधाएं विभिन्न कार्यों जैसे शिक्षा व सेवा केन्द्रों, स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, बाजार, विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वच्छता कार्यालय, दुकानों, बैंक पाठशालाएं आदि के रूप में 193 गांवों मे बिखरी हुई है।

इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं व सेवा केन्द्रों में रूपान्तरण तथा इनकी स्थिति व आवयकताओं का अध्ययन करने हेतु, अध्ययन क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यों व सुविधाओं के आधार पर केन्द्रीयता सूचकांक व न्यूनतम जनसंख्या स्तर को सामाजिक सुविधाओं की स्थापना हेतु ज्ञात किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले की नांवा तहसील है। तहसील की कुल जनसंख्या 336963 है। इसमें 79.57 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों की है। नांवा तहसील, जिले की पिछड़ी तहसीलों में गिनी जाती है। ये तहसील अल्प विकसित संक्रामी क्षेत्र हैं। इसमें समन्वित विकास हेतु समस्याओं को खोज कर वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाना है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का चुनाव किया जाना मेरे शोध का मुख्य लक्ष्य है। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास होने पर भी कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जो मुख्यतः वहाँ के भौगोलिक परिवेश पर निर्भर होती हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में भौगोलिक परिवेश पर निर्भर होती है। अतः अध्ययन क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में भौगोलिक वातावरण के तत्त्वों का अध्ययन करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। नांवा तहसील राजस्थान नागौर जिले की एक प्रशासनिक इकाई है, जो नागौर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 27^0 22′ 38″ व 26^0 53′35″ उत्तरी अक्षांशों

तथा 75^0 21′57″ व 75^0 03′18″ पूर्वी देशान्तरों के मध्य है। इसके उत्तर व उत्तर–पूर्व में सीकर जिला, उत्तर–पश्चिम में डीडवाना तहसील, दक्षिण–पश्चिम में मकराना तहसील व परबतसर तहसील, दक्षिण–पूर्व में जयपुर जिला स्थित है। यह तहसील 1521.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है तथा तहसील की वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या 3,36,963 है। यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 268146 है तथा शहरी जनसंख्या 68817 है। जनसंख्या घनत्व 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तहसील में सम्पूर्ण ग्रामों की संख्या 193 है।

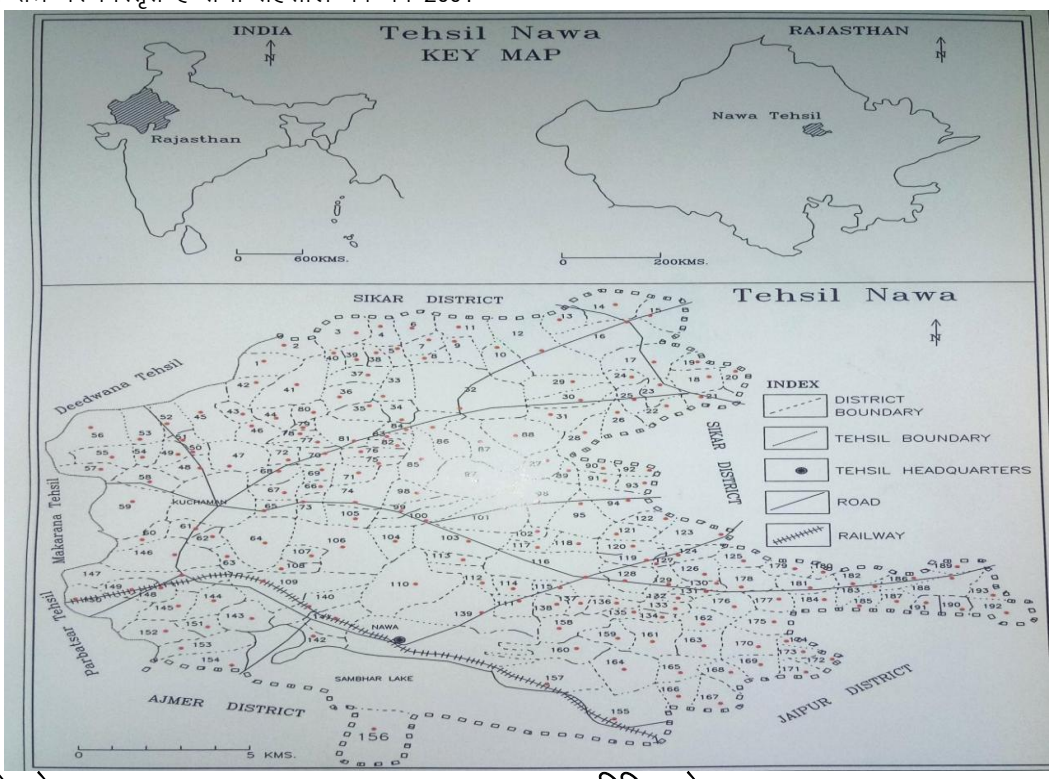

अध्ययन के उद्देश्य

1. अध्ययन क्षेत्र के शिक्षा स्वरूप का अध्ययन करना।
2. अध्ययन क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र की यातायात व संचार सेवाओं का अध्ययन करना।
4. अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों का अध्ययन करना।
5. अध्ययन क्षेत्र में विद्युतीकरण सेवा का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनायें

1. अध्ययन क्षेत्र की बदलती अवसंरचनात्मक सुविधाओं के परिणाम स्वरूप आय सुख–सुविधाऐं निरन्तर बढ़ रही है।
2. बढ़ती हुई आम सुख सुविधाओं के कारण अध्ययन क्षेत्र का भौतिक स्वरूप बदल रहा है।

विधि तंत्र एवं आँकड़ों का संकलन

प्रस्तुत शोध पत्र में आँकड़ों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक प्रकार से किया गया है, प्राथमिक आँकड़े प्रश्नावली, साक्षात्कार व अनुसूची के माध्यम से लिये गये हैं तथा द्वितीयक प्रकार के आँकड़ों का संकलन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा प्रकाशित व अप्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं तथा सम्बन्धित शोध पत्रों से लिया गया है। शोध पत्र में आवश्यकतानुसार सारणीयन तथा उनका विश्लेषण कर आरेख, रेखाचित्र व मानचित्रों द्वारा स्पष्ट एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

साहित्यावलोकन

एल. एस. भट्ट ने 1972 में करनाल जिले के नगरीय विकास प्रतिरूप पर भारतीय भूगोल परिषद् में अपना शोध–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें करनाल जिले के नगरीय सुख–सुविधाओं यथा–शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बाजार तथा जलापूर्ति आदि का उल्लेख किया।

बी. सी. मेहता ने 1978 में प्रादेशिक जनसंख्या वृद्धि पर राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में एक शोध पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय विषमताओं जैसे– जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, घनत्व, वृद्धि दर तथा उद्योगों का उल्लेख किया गया।

आर. एन. दूबे ने 1988 में आर्थिक विकास एवं नियोजन पुस्तक का प्रकाशन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली से किया, जिसमें भारत देश के आर्थिक विकास तथा प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया।

नांवा तहसील में शिक्षा का स्वरूप

शिक्षा मानव जीवन की गुणवत्ता का प्रथम पहलू है। शिक्षा राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज में बदलते मूल्यों को स्वीकार करता है एवं समाज में एक नई व्यवस्था को स्थापित करने व पुरानी परम्पराओं को परिवर्तित करने के विचारों को विकसित करता है। शिक्षा द्वारा गुणवत्ता, कार्यक्षमता में

वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे रोजगार व आय के साधन बढ़ने से समाज, राष्ट्र व क्षेत्र का जीवन स्तर उन्नत होगा और ये विकासमान होंगे। नावां तहसील में शिक्षा के अन्तर्गत चार प्रकार के विद्यालयों को शामिल किया गया है –

1. प्राथमिक विद्यालय
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय
3. माध्यमिक विद्यालय
4. उच्च माध्यमिक विद्यालय

उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को शैक्षणिक स्तर की सुविधाएं प्रदान करता है, और यदि ये एक ही भवन में संचालित होती है, ऐसी स्थिति में केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय को अधिक अंकमान दिया गया है। यदि एक ग्राम में माध्यमिक विद्यालय के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय भी है, जो कि माध्यमिक विद्यालय के भवन में संचालित नहीं होता है बल्कि वह स्वतन्त्र रूप से अलग स्थित है, तब इन दोनों स्थानों को अलग–अलग अंकमान दिया गया है।

नांवा तहसील की शैक्षिक संस्थाओं का वितरण (2011)

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्थाओं की सं0	सुविधा उपलब्ध ग्रामों की सं0	सुविधा उपलब्ध ग्रामों का प्रतिशत
1	प्राथमिक विद्यालय	288	187	96.89
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	90	78	40.41
3	माध्यमिक विद्यालय	21	21	10.88
4	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	5	5	2.59

स्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, नागौर

उपर्युक्त तालिका अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं को प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5 है। ये विद्यालय 5 गाँवों में स्थित हैं तथा इनसे सुविधा प्राप्त गांवों का प्रतिशत केवल 2.59 है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 21 है। इनसे लाभान्वित गांवों का प्रतिशत 10.88 है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 90 है। इन विद्यालयों से 78 गाँव सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इनसे सुविधा प्राप्त गांवों का प्रतिशत 40.41 है। नांवा तहसील में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 288 है तथा ये 187 गाँवों में स्थित है। ऐसे सुविधा प्राप्त गाँव 96.89 प्रतिशत हैं। अध्ययन क्षेत्र के 5 गाँव शिक्षा सुविधा से पूर्णत वंचित है।

नांवा तहसील में शिक्षा विस्तार के स्वरूप आधारित प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत सर्वप्रथम वर्ष 1967 में उदयपुर में किसान क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। 2 अक्टूबर, 1978 को राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत 20016 केन्द्रों से 6.08 लाख प्रौढ़ों को साक्षर किया गया। यह निदेषालय महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किये हुए है। इसके द्वारा 7641 केन्द्र केवल महिलाओं के लिए है। वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा को साक्षर भारत कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। 8 सितम्बर, 2009 को साक्षर भारत कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया गया। इसमें मूल साक्षरता को सुधारने के लिए स्वयं सेवा आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें 11वीं योजना समाप्ति तक 80 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने तथा साक्षरता में क्षेत्रीय विषमता को कम करने और साक्षरता में महिला–पुरूष के अंतर को कम करने की अभिकल्पना की गई है।

साक्षर भारत कार्यक्रम देष के 365 जिलों व वामपंथी चरमपंथी से अत्यधिक प्रभावित 35 जिलों को भी प्रौढ़ महिला साक्षरता दर पर ध्यान दिए बिना शामिल किया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2009–10 के दौरान यह मिषन 8100 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 19 राज्यों के 197 जिलों तक विस्तृत किया गया है। इन जिलों में 3.83 करोड़ निरक्षर लोगों को इससे लाभ हुआ। वर्ष 2010–11 के दौरान लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों में 1.77 करोड़ निरक्षरों को इस योजना में लाने के लिए इसमें 118 जिलों को और शामिल किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में साक्षर भारत कार्यक्रम कुचामन पंचायत समिति के माध्यम से पंचायत समिति की 55 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित है। परिशिष्ट संख्या 2.2 से कुचामन पंचायत समिति में स्थित 55 ग्राम पंचायतों में अध्ययन कर रहे शिक्षार्थियों को दर्शाया गया है। इसके अनुसार कुचामन पंचायत समिति में 1926 व्यक्ति साक्षर भारत कार्यक्रम में अध्ययनरत हैं, जिसमें 482 पुरूष व 1444 महिलाऐं सम्मिलित हैं। सर्वाधिक प्रौढ़ व्यक्ति खाखड़की ग्राम पंचायत में 379 हैं तथा न्यूनतम शून्य संख्या इण्डाली ग्राम पंचायत में है। इसी प्रकार सर्वाधिक महिला प्रौढ़ शिक्षार्थी, 293 महिलाएं खाखड़की ग्राम पंचायत में हैं तथा सर्वाधिक पुरूष प्रौढ़ शिक्षार्थी, 100 पुरूष पाँचवा ग्राम पंचायत में है।

नांवा तहसील में स्थित ग्राम पंचायतवार असाक्षर व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है। कुचामन पंचायत समिति में 35 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर प्रौढ़ों की कुल संख्या 42834 व्यक्ति है। जिसमें 14101 पुरूष व 28733 महिलाएं शामिल हैं। सर्वाधिक असाक्षर प्रौढ़ों की संख्या 1878 व्यक्ति, मीण्डा ग्राम पंचायत में व न्यूनतम प्रौढ़ व्यक्ति 278, खाखड़की ग्राम पंचायत में है। सर्वाधिक पुरुष असाक्षर व्यक्ति 623 व सर्वाधिक असाक्षर महिलाऐं 1255, मीण्डा ग्राम पंचायत में हैं। इसी प्रकार न्यूनतम असाक्षर पुरुष 49 व्यक्ति अड़कसर ग्राम पंचायत में है तथा न्यूनतम असाक्षर महिलाऐं 182 भूणी ग्राम पंचायत में है।

स्वैच्छिक क्षेत्र के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को दो स्कीमों अन्तर्गत 1. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र

में स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता, 2. जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से सहायता प्रदान करना। वर्ष 2009 से इन्हें मिलाकर प्रौढ़ शिक्षा और कौषल विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की स्कीम के रूप में संशोधित किया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य साक्षर भारत के समग्र क्षेत्र के तहत कार्यात्मक साक्षरता कौशल विकास और सतत् शिक्षा को प्रौढ़ों के मध्य प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों में स्वैच्छिक क्षेत्र की विस्तारी और गहन सहभागिता प्राप्त करना है। स्कीम में तीन घटकों अर्थात् राज्य संसाधन केन्द्र, जन शिक्षण संस्थान, और स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायताओं को शामिल किया गया है। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर शहरों में 2 राज्य संसाधन केन्द्र स्थित है।

नांवा तहसील में स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेष है। स्वस्थ व्यक्ति ही उद्योग को या कृषि कार्य को अपना पूर्ण योगदान देकर उत्पादन बढ़ा सकता है। तहसील में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों से 6 गाँव चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केन्द्रों की संख्या 35 है जिनसे सेवा प्राप्त गाँव 18.13 प्रतिशत हैं। तहसील में 7 परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित हैं जिनसे सेवा प्राप्त गाँव 3.62 प्रतिशत हैं। तहसील में कुकनवाली व लालास में 2 प्रसूति गृह स्थापित हैं। इनमें सेवा प्राप्त गाँव 1.03 प्रतिशत हैं।

नांवा तहसील में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का वितरण (2011)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	केन्द्रों की संख्या	सुविधा उपलब्ध गाँवों की संख्या	सुविधा उपलब्ध गाँवों का प्रतिशत
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	6	6	3.10
2	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र	35	35	18.13
3	परिवार कल्याण केन्द्र	7	7	3.62
4	प्रसूति गृह	2	2	1.03

स्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, नागौर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं। तहसील में इन सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए।

नांवा तहसील में यातायात एवं संचार सुविधाएं

नांवा तहसील में रेल व सड़क यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तहसील मुख्यालय नांवा रेल्वे मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। नांवा तहसील में 7 रेल्वे स्टेशन हैं। तहसील के 6 गाँव रेल्वे मार्गों से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी रेल्वे की जयपुर–जोधपुर बड़ी रेल्वे लाईन तहसील के दक्षिणतम भाग की सीमा के सहारे–सहारे गुजरती है। इसके अलावा तहसील में फुलेरा–रींगस मीटर गेज लाईन ठीकरिया खुर्द व भींवपुरा गाँवों से गुजरती है। अब इसका अमान परिवर्तन किया जा रहा है। नांवा तहसील में वायुयान परिवहन सेवा उपलब्ध नही है। यद्यपि कभी–कभी आवश्यकतानुसार हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपेड बना लिए जाते हैं। सड़क गम्यता, क्षेत्र के आर्थिक–सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। अध्ययन क्षेत्र में 95 गाँव सड़क मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। शेष ग्राम कच्चे मार्गों से सम्बद्ध हैं। अध्ययन क्षेत्र में 3 राजमार्ग गुजरते हैं। पहला किशनगढ़–हनुमानगढ़ राजमार्ग संख्या 7, द्वितीय जयपुर–कुचामन राजमार्ग संख्या 2 तथा तीसरा जोबनेर–कुचामन राजमार्ग संख्या 19 है। पहला राजमार्ग संख्या 7 तहसील के दक्षिण–पश्चिम में किशनगढ़–परबतसर–डीडवाना तहसीलों को जोड़ता है। इस राजमार्ग की लम्बाई तहसील में 21 किलोमीटर है। राजमार्ग संख्या 2 अध्ययन क्षेत्र को सांभर तहसील से जोड़ता है। इस राजमार्ग की तहसील में लम्बाई 44.2 किलोमीटर है। राजमार्ग संख्या 19 तहसील की कुचामन पंचायत समिति को सीकर की दाँता तहसील से जोड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी लम्बाई 31.9 किलोमीटर है। तहसील में कुल राजमार्गों की लम्बाई 97.1 किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र में एक मुख्य जिला सड़क भी स्थित है जो कुचामन पंचायत समिति को सीकर जिले से जोड़ती है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी कुल लम्बाई 38 किलोमीटर है। आबाद ग्रामों (193) में से 95 ग्राम ही पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं। अध्ययन क्षेत्र की सड़क गम्यता के भौगोलिक वितरण को प्रदर्शित करता है। अध्ययन क्षेत्र में निजी जीप व गाड़ियाँ, मोटर साईकिल व ऑटोरिक्शा, सार्वजनिक एवं निजी वाहन अनुबन्धित एवं टैक्सी वाहन संचालित वाहनों के मुख्य प्रकार हैं। तहसील में राज्य मार्गों व मुख्य जिला मार्ग पर सामान्य बस सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध है। निगम की नियमित बसें जयपुर–नागौर एवं सीकर–अजमेर तथा अजमेर–नागौर जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर चलती हैं।

अध्ययन क्षेत्र में डाकघर, तारघर एवं दूरभाष की सुविधाएं सम्मिलित रूप में है। तहसील में 57 डाकघर स्थापित हैं। डाकघर से सेवा प्राप्त गाँव 29.53 प्रतिशत है। तहसील में 5 डाक एवं तारघर स्थापित है। कुल गांवों में से डाक एवं तारघर की सुविधा प्राप्त गाँव 2.59 प्रतिशत हैं। तहसील में 730 दूरभाष लगे हुए हैं तथा 82 गाँव दूरभाष की सेवा प्राप्त गाँव हैं। इनसे सेवा प्राप्त गाँव का प्रतिशत 42.48 प्रतिशत है।

नांवा तहसील में डाक एवं संचार संस्थाओं का वितरण (2011)

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्थाओं की संख्या	सुविधा उपलब्ध ग्रामों की संख्या	सुविधा उपलब्ध ग्रामों का प्रतिशत
1	डाकघर	57	57	29.53
2	डाक एवं तारघर	5	5	2.59
3	दूरभाष	730	82	42.48

स्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, नागौर

उपर्युक्त तालिका के विष्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 144 गाँव ही डाक एवं संचार सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। बाकी गाँव संचार सुविधाओं से वंचित हैं। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में संचार सुविधाओं का विस्तार कम है।

नांवा तहसील में बाजार सुविधाएं

बाजार सुविधाओं के अन्तर्गत छोटी दुकान एवं उप–बाजार केन्द्र शामिल हैं। छोटी दुकानों से तात्पर्य उन दुकानों से है जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय करती है। शहरों की गाँवों से अधिक दूरी के कारण ग्रामीण अधिकांशतः इन दुकानों से ही वस्तुओ का क्रय करते हैं। उप–बाजार केन्द्र से तात्पर्य ऐसे बाजार केन्द्रों से है, जहाँ पर सब्जी मण्डी, कृषि उपज मण्ड एवं अन्य वस्तुओं का बाजार लगता है।

नांवा तहसील के बाजार केन्द्रों का वितरण (2011)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	केन्द्रों की संख्या	सुविधा उपलब्ध गाँवों की संख्या	सुविधा उपलब्ध गाँवों का प्रतिशत
1	छोटी दुकान	776	145	75.12
2	उप बाजार केन्द्र	2	2	1.03

स्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, नागौर

तहसील में दो उप–बाजार केन्द्र हैं। पहला कुचामन सिटी कस्बे में व दूसरा नांवा सिटी कस्बे में है। कुचामन कृषि उप मण्डी जिले की महत्वपूर्ण बड़ी मण्डियों में से एक है यहाँ गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मूंगफली, मूंग, चँवला, बाजरा, मोठ इत्यादि महत्वपूर्ण उपजें हैं। कुचामन की सब्जी मण्डी अध्ययन क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नांवा सब्जी मण्डी कुचामन से छोटी सब्जी मण्डी है।

इन मण्डियों से कृषि और पशु उत्पाद जैसे घी, चर्म, ऊन, बाल, हड्डी इत्यादि के अतिरिक्त तहसील के बाहर महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे गेहूँ, सरसों, मूँग, मोठ आदि का निर्यात होता है। अध्ययन क्षेत्र में 145 गाँवों में 776 छोटी दुकानें हैं, जिनसे 75.12 प्रतिशत गाँव सेवाएं प्राप्त कर रहें हैं। तहसील में कुचामन सिटी व नांवा सिटी कस्बों में ही उप–बाजार केन्द्र स्थित होने के कारण तहसील का मुख्यतः कृषि–विपणन कार्य इन्हीं दोनों कस्बों में होता है।

नांवा तहसील में विद्युत सेवाएं

किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में विद्युत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उद्योग धन्धे, कृषि, संचार आदि विद्युत ऊर्जा पर अवलम्बित है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जीवन की कायापलट के लिए आधारभूत आवश्यकता एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए एक प्रमुख कारक है। अध्ययन क्षेत्र में 192 गाँव विद्युत सुविधा से जुड़े हुये हैं। केवल एक गाँव को छोड़कर सभी गाँवों में विद्युत सुविधा प्राप्त है।

नांवा तहसील में विद्युत सुविधा वितरण (2011)

क्र.सं.	विद्युत उपयोग प्रयोजन	सुविधा उपलब्ध गाँवों की संख्या	सुविधा उपलब्ध गाँवों का प्रतिशत
1	घरेलू प्रयोजन	192	99.48
2	कृषीय प्रयोजन	142	73.57

स्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, नागौर

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 192 गाँव घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत का उपभोग करते हैं। घरेलू प्रयोजन के लिए विद्युत उपभोग 99.48 प्रतिशत है।

गाँव कृषीय प्रयोजन के लिए विद्युत उपभोग करते हैं। कृषीय प्रयोजन हेतु विद्युत उपभोग तहसील में 73.57 प्रतिशत है। यद्यपि तहसील के 193 गाँवों में से 192 गाँवों को विद्युत सुविधा प्राप्त है। परन्तु बिजली की आपूर्ति व्यवधान रहित नहीं है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में नांवा तहसील की क्षेत्रीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। जिनमें शिक्षा व सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, यातायात एवं संचार, बाजार, विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वच्छता, दुकानें एवं बैंक आदि का अध्ययन किया गया हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नांवा तहसील को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यालयों के रूप में उल्लेखित किया गया है। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा का भी अध्ययन किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का उल्लेख किया गया है। यातायात व संचार की दृष्टि से कच्ची व पक्की सड़कों का उल्लेख किया गया है। अतः निष्कर्षतः नांवा तहसील के सन्दर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि तकनीकी युग ने किया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *जगदीश गहलोत (1980), "राजस्थान का सामाजिक जीवन" हिन्दी साहित्य मंदिर, जोधपुर।*
2. *आर.एन. दुबे तथा वी.एस. सिन्हा (1998), "आर्थिक विकास एवं नियोजन" नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।*
3. *बी.एन. दाउदयाल (2012), "राजस्थान जिला गजेटियर" जयपुर।*
4. *बसंत मोघे (2011), "राजस्थान में कृषि उत्पादन" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।*
5. *जिला सांख्यिकी रूपरेखा, (2011) जिला – नागौर।*
6. *भारतीय जनगणना विभाग, राजस्थान जयपुर।*